

सिविल विविध

न्यायमूर्ति बलराज तुली के समक्ष

गुरजदयाल सिंह बावा, याचिकाकर्ता

बनाम

उद्योग निदेशक, हरियाणा, आदि- उत्तरदाता।

1968 की सिविल रिट संख्या 3686

24 फरवरी, 1971

*पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II - नियम 5.32 - पंजाब उद्योग विभाग (राज्य सेवा वर्ग III) नियम (1956) - नियम 7 (2) - 1951 में उद्योग निदेशक द्वारा नियुक्त निरीक्षक भार और माप - 1956 के नियमों के लागू होने के बाद, उसका नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य बाट और माप निरीक्षक बन जाता है— उद्योग निदेशक द्वारा जारी नियम 5.32 के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की सूचना— ऐसी सूचना- क्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी की गई वैध सूचना है।*

*अदालत ने कहा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड दो के नियम 5.32 के तहत जारी तीन महीने का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें किसी सरकारी अधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है। जहां किसी व्यक्ति को 1951 में उद्योग निदेशक द्वारा इंस्पेक्टर वेट्स एना मेजर्स नियुक्त किया जाता है, लेकिन पंजाब उद्योग विभाग (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1956 के प्रवर्तन पर, उसका नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य बाट और माप निरीक्षक बन जाता है, उद्योग निदेशक द्वारा जारी सेवानिवृत्ति की सूचना मान्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई है। केवल यह तथ्य कि नियमों के नियम 7(2) के अंतर्गत बाट एवं माप निरीक्षक की नियुक्ति उद्योग निदेशक के अनुमोदन से बाट-तौल नियंत्रक द्वारा की जानी होती है, उद्योग निदेशक को निरीक्षकों, बाट एवं मापों का नियुक्ति प्राधिकारी नहीं बनाता है। नियुक्ति प्राधिकारी भार और माप नियंत्रक बना रहता है।* (पैरा 4)

*भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि सर्टिओरारी, मंडामस या किसी अन्य उपयुक्त, आदेश, रिट या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए। एफ/73/14-वी/41192-ए, दिनांक 19 अगस्त, 1968, सेवा नियमों के प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया।*

*के.पी. भंडारी और आई. बी भंडारी वकील, याचिकाकर्ताओं की ओर से,।*

*सी. डी. दीवान, एल्डिशनल एडवोकेट-जनरल, हरियाणा और एस.पी. जैन, वकील, उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति तुली —(1) याचिकाकर्ता दिसंबर, 1940 में सरकारी डाइंग एंड कोलिको प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट, शाहदरा, लाहौर में स्टोर कीपर के रूप में सेवा में शामिल हुए। जून, 1942 में, उन्हें जूनियर क्लर्क स्टोर परचेज ऑफिस, लाहौर में नियुक्त किया गया और जून, 1944 में, उन्हें दुकानों के निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया था। देश के विभाजन के बाद, उन्हें 1951 में पंजाब के उद्योग निदेशक के एक आदेश से जुलुंदूर में इंस्पेक्टर, भार और माप नियुक्त किया गया था। उन्होंने उस पद पर काम करना जारी रखा और उन्हें 19 अगस्त, 1968 को उद्योग निदेशक, हरियाणा द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें पूर्ववर्ती पंजाब राज्य

के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप आवंटित किया गया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि वह 31 दिसंबर 1968 से 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त होंगे। इस नोटिस को वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

2. हरियाणा राज्य के उद्योग विभाग के उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से की गई पहली दलील यह है कि उन्हें 1951 में उद्योग निदेशक द्वारा निरीक्षक, भार और माप के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन पंजाब उद्योग विभाग (राज्य सेवा वर्ग III) नियम, 1956 (इसके बाद नियम कहा जाता है) के प्रवर्तन के बाद, उनकी नियुक्ति प्राधिकारी मुख्य भार और माप निरीक्षक थे। और पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड, II के नियम 5.32 के तहत 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त करने का नोटिस नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, जिसे पंजाब भार और माप प्रवर्तन अधिनियम की धारा 15 के तहत भार और माप निरीक्षक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। 1958 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है)। प्रतिवादियों द्वारा यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता उक्त नियमों द्वारा शासित होता है जिसके तहत भार और माप निरीक्षक का नियुक्ति प्राधिकारी भार और माप का मुख्य निरीक्षक होता है। तथापि, ऐसी नियुक्ति उद्योग निदेशक के अनुमोदन से की जानी चाहिए, जैसा कि नियमों के नियम 7(2) में निर्धारित किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना सही है कि 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर याचिकाकर्ता को तीन महीने सेवानिवृत्त होने का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया जाना था, लेकिन निर्धारण का मुद्दा यह है कि किसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाए। जिस अधिकारी ने वास्तव में 1951 में उनकी नियुक्ति की थी या सेवा नियमों में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी थे, इस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि सेवा नियमों या अधिनियम में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी को नियम के तहत नोटिस जारी करना होगा;

पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II की धारा 5.32, न कि वह प्राधिकारी जिसने मूल रूप से

संबंधित सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया था। यह विशेष रूप से पुनर्गठित राज्यों के

मामले में है, और मैं इस दृष्टिकोण से पंजाब राज्य और अन्य *बनाम*

*संत सिंह देवा सिंह*(1) के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ के निर्णय द्वारा समर्थित हूं। इसलिए, नोटिस मुख्य भार और माप निरीक्षक द्वारा जारी किया जाना था, जिसका पदनाम अब उद्योग निदेशक द्वारा नहीं, बल्कि भार और माप नियंत्रक में बदल दिया गया है।

4. केवल यह तथ्य कि नियमों के नियम 7(2) के अंतर्गत भार एवं माप निरीक्षक की नियुक्ति उद्योग निदेशक के अनुमोदन से भार -तौल नियंत्रक द्वारा की जानी होती है, उद्योग निदेशक को निरीक्षकों, भार एवं मापों का नियुक्ति प्राधिकारी नहीं बनाता है। नियुक्ति प्राधिकारी भार और माप नियंत्रक बना रहता है। यह विचार *उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप द्वारा असम राज्य बनाम कृपानाथ सरमा और अन्य*(2) में व्यक्त किया गया है। मुझे प्रतिवादियों के वकील द्वारा दी गई इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता कि उद्योग निदेशक नियंत्रक, भार और माप से उच्च रैंक का प्राधिकारी है, और इसलिए, उद्योग निदेशक द्वारा जारी नोटिस सही था। नियम 5.32 *पूर्वोक्त* केवल एक नियुक्ति प्राधिकारी की बात करता है, न कि "नियुक्ति प्राधिकारी के पद से नीचे के प्राधिकारी की"। अतः, मेरी राय है कि नोटिस या तो नियंत्रक, भार और माप या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि उद्योग निदेशक द्वारा।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया दूसरा बिंदु यह है कि याचिकाकर्ता को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश पारित करते समय, उद्योग निदेशक ने बाहरी मामलों को ध्यान में रखा, अर्थात्, याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप, जिनमें से उसे उचित जांच के बाद दोषमुक्त कर दिया गया था। मुझे इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता। याचिकाकर्ता को जारी नोटिस में उसकी ओर से और नियम 5.32 के तहत किसी भी कदाचार का उल्लेख नहीं है। किसी सरकारी अधिकारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकारी में पूर्ण है और इस तरह के नोटिस जारी करने के कारणों को रिकॉर्ड करना अनिवार्य नहीं है।

(1) AIR. 1964 Pb. 480.

(2) A.I.R. 1967 S.C. 459.

न ही याचिकाकर्ता को जारी नोटिस को इस आधार पर दुर्भावनापूर्ण कहा जा सकता है नियुक्ति प्राधिकारी को यह तय करना होता है कि लोक सेवक को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा में बनाए रखा जाए या नहीं और यह उद्योग निदेशक के लिए खुला था, यदि वह सक्षम प्राधिकारी था, तो वह याचिकाकर्ता की ईमानदारी और अखंडता की प्रतिष्ठा सहित सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रख सकता था। यहां तक कि अगर याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, तो इसका मतलब यह नहीं था कि उसका सेवा रिकॉर्ड ऐसा था कि उसे 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए नहीं कहा जा सकता था।

7. याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए पहले बिंदु के संबंध में ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और हरियाणा के उद्योग निदेशक द्वारा 19 अगस्त, 1968 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31 दिसंबर, 1968 से सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ता को जारी नोटिस को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता अपनी लागत का हकदार होगा। वकील की फीस 100.00 रुपये।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा